जुड़े हुए उनके जो पांच इंटरेस्ट्स हैं, उनसे जुड़े हुए संगठन बनाये, जिनके साथ भारत सरकार का suspension of operation हुआ है और किसी के साथ बातचीत भी हो रही है, वह आपको पता है। बातचीत के साथ-साथ कई ऐसे केसेज़ भी हैं, जो दर्ज किए गए थे, उन केसेज़ को भी विद्ड्रॉ किया गया, क्योंकि वह प्रावधान है कि जब बातचीत होती है या कोई सरेंडर करता है, तो जब वह सरेंडर करता है, तो उसके खिलाफ केसेज़ भी हम विद्ड्रॉ करते हैं। लेकिन कोई-कोई ऐसा भी है, जिसमें केसेज़ बने रहते हैं, क्योंकि बातचीत जब तक कम्प्लीट नहीं हुई, तब तक कोई-कोई केस बचा रहता है। इसलिए आदिवासी संगठन, जितने भी नाम माननीय सदस्य ने लिये हैं, उनके अलावा भी असम में जितने भी संगठन हैं, सब के साथ भारत सरकार असम सरकार के सहयोग से यह कोशिश कर रही है कि सभी मेनस्ट्रीम में आ जाएँ। अगर सभी मेनस्ट्रीम में आ जाएँगे, तो उनके जो मुद्दे हैं, उनको भी ध्यान में रखेंगे और उनके खिलाफ जो केसेज़ हैं, वे भी खत्म हो जाएँगे।

श्री लाल सिंह वडोदियाः माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आतंकवादियों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए सामाजिक संनिष्ठ लीडर्स द्वारा आतंकवादियों से संवाद करके इनकी समस्याओं को समझ कर और सरकार को साथ रख कर नया आतंकवादी बनने से रोका जाए, इसके लिए क्या सरकार कुछ प्रयास करना चाहती है?

श्री किरन रिजिजुः सर, यह तो जाहिर सी बात है कि सरकार यही चाहेगी कि जो आतंकवादी संगठन हैं, वे सारे खत्म हो जाएं और नया संगठन उत्पन्न भी न हो। यह हर सरकार का हमेशा ही प्रयास रहता है, इसलिए जो संगठन चल रहे हैं, वे अगर बातचीत के लिए तैयार होते हैं, तो सरकार उनको बातचीत के लिए जरूर आमंत्रित करती है, लेकिन इस संबंध में गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लीयर है कि we are ready for peace talks, but you must cease violence. जब तक आप हथियार लेकर सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ जंग छेड़ते रहेंगे या लड़ाई करते रहेंगे, तब तक आपसे बातचीत नहीं होगी। अगर आपको सरकार से बातचीत करनी है, तो आपको surrender करना पड़ेगा। इसके अलावा इस प्रकार के नए संगठन उत्पन्न न हों, इसके लिए तो हम यहां से कोई एक definite plan तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अलग-अलग तरीके से इस तरह के प्रयास हो रहे हैं कि इस तरह का और संगठन इस देश में खड़ा न हो।

Attacks on railway tracks

*212. SHRI SANJAY RAUT: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government has thoroughly investigated through various intelligence agencies, the recent attacks on railway tracks;

(b) if so, the details thereof indicating the findings thereof;

(c) whether it is a fact that ISI and Pakistan sponsored agencies are involved in such attacks; and

(d) if so, the details of steps taken/proposed to be taken by Government for securing the country's huge railway network?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HANSRAJ GANGARAM AHIR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Central Government had received information regarding suspected criminal interference in railway tracks in different parts of the country and some rail accidents caused due to such activities. Keeping in view the gravity of the offenses and suspected involvement of anti-national elements and extremists in some of these incidents, the Central Government has entrusted investigation of the following cases to NIA:—

(i) FIR No. 19/2016 dated 01.10.2016 registered at PS Rail Raxaul, District Muzaffarpur, Bihar regarding planting of pressure cooker IED in railway track at Ghorasan, Motihari.

(ii) FIR No. 55/2016 dated 21.11.2016 registered at PS GRP Bhimsen, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh regarding accident of train no. 19321 (Indore-Patna Express) near Pukhraya, Kanpur Dehat.

(iii) FIR No. 6/2017 dated 22.01.2017 registered at PS Vizianagaram District GRP Vijaywada, Andhra Pradesh regarding accident of train no. 18448 (Jagdalpur-Bhubaneshwar Express) near Kuneru.

(c) The cases are still under investigation.

(d) Policing being a State subject, prevention of crime, registration of cases, their investigation and maintenance of law and order in Railway premises as well as on running trains and security of railway tracks, tunnels and bridges are the primary responsibility of the State Governments, which they discharge through Government Railway Police (GRP)/Civil Police. However, Railway Protection Force (RPF) supplements the efforts of GRP by providing better protection and security of passenger area and passengers and for matters connected therewith.

The Central Government has issued advisory to all State Governments/UT Administrations on 31.01.2017 requesting them to beef up intelligence mechanism and security set up in railway installations and to take all precautionary and preventive measures in coordination with the Chief Security Commissioners/Senior Divisional Security Commissioners of the railway divisions to prevent sabotage/damage to railway installations. Video Conferencing was conducted on 27.02.2017 with DGsP/IGsP of States/UTs regarding strengthening of safety and security of railway installations which was addressed by Minister of Railway and Minister of State for Home Affairs.

Safety drives have also been launched by the Zonal railways to ensure that all safety precautions laid down by the Manuals are followed. Security Help Line number 182 has been made operational over Indian Railways for security related assistance to passengers in distress. An Integrated Security System consisting of surveillance of vulnerable stations through Close Circuit Television Camera Network, Access Control etc. has been sanctioned to improve surveillance mechanisms over 202 railway station. Sniffer Dog Squads are utilized at some important stations for anti-sabotage checks.

श्री संजय राउतः सर, मेरा प्रश्न रेलवे की सुरक्षा के बारे में है और गृह मंत्रालय उसका जवाब दे रहा है।

सर, हिन्दुस्तान में करीब चार परसेंट से भी ज्यादा लोग हर दिन रेल से यात्रा करते हैं और उनमें से हर यात्री को आज हर वक्त किसी न किसी हादसे का डर सता रहा है। कभी रेलवे ट्रैक पर रॉड्स रखे जाते हैं, कभी ट्रैक tampering की जाती है और दो-चार महीने में इस प्रकार की घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं। अब सुरक्षित यात्रा से लोगों का विश्वास उठ गया है।

सर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और मुम्बई तक, इस प्रकार से जो ट्रक tampering की घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं, उनसे लोगों के मन में डर है, उससे accidents हो रहे हैं। यह terrorism का मामला है। मैंने जवाब में देखा है। 2014 में चेन्नई में बेंगलुरु-गुवाहाटी एक्सप्रेस बम ब्लास्ट हुआ, उसमें सबसे पहले आईएसआई का नाम आया, कानपुर के निकट पुखरायां में जो हादसा हुआ, उसमें भी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन का नाम आया, आंध्र प्रदेश के विजयनगर में कुनेरू में जो ट्रेन एक्सिडेंट हुआ, उसमें भी आईएसआई का नाम आया है।

सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस देश में आतंकवाद, terrorism बढ़ाने के लिए, देश को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान का नेपाल बॉर्डर की तरफ से कोई नया मॉडल या स्लीपर सेल बन गया है? अगर ऐसा है, तो सरकार के पास इसके बारे में क्या जानकारी है? इसके साथ ही मैंने जिन चार ट्रेन एक्सिडेंट्स का जिक्र किया है, जिनकी जांच नेशनल जांच एजेंसी कर रही है, उनके बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं यानी यह क्या है?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति महोदय, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उनमें से ज्यादातर का जवाब दिया गया है। उसके बावजूद भी सामान्य जनता के मन में यह भावना उत्पन्न हुई है और उन्हें रेल यात्रा खतरे की लगती है। आपने अपने प्रश्न में यह बताया कि हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं, वे बड़ी-बड़ी घटनाएं हैं। होम मिनिस्ट्री ने इस संबंध में रेल मंत्रालय से संपर्क बनाते हुए उसको कुछ गाइडलाइन्स दी हैं, एडवाइज़री दी हैं और रेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी रेलवे जोनल अधिकारियों को मैन्युल के अनुसार सेफ्टी के सारे नियमों का पालन करने के संबंध में सूचना भेजी गई है। यह भी बताया गया है कि उसका तरीके से पालन किया जाए। इसके साथ ही कुछ सुरक्षा के उपाय भी बताए गए हैं। उसमें 182 हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है। अगर कहीं खतरे की बात आती है, तो 182 पर इसकी सूचना दी जा सकती है।

कुछ sensitive railway stations हैं, ऐसे 202 स्टेशनों का चयन हुआ है, जहां पर सीसीटीवी एसेट कंट्रोल बनाए गए हैं, उनमें सुधार किया जा रहा है। साथ ही जहां पर anti-sabotage

check in की आवश्यकता है, वहां पर अभी डॉग स्क्वॉड की व्यवस्था की जा रही है। इसको बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा रहा है।

इसके साथ ही हमने हाल ही में रेल मंत्री के साथ मिल कर DGsP/IGsP लेवल के अधिकारियों के साथ रेल प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़/क्षित को रोकने के संबंध में video conferencing की है और सभी स्टेट के डीजी लेवल के अधिकारियों को यह सूचना दी है कि हर स्टेट में जो आरपीएफ है यानी रेलवे पुलिस है, वह उसके साथ मिल कर काम करे। इसके साथ, Police modernization की जब बात आती है, सभी States को अपने यहां काम करने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए, नए-नए equipments लेने की जरूरत होती है, उसमें भी केंद्र सरकार Police modernization के लिए आर्थिक सहायता देती है। इसके अलावा, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है, तीन स्थानों पर ISI के involvement की संभावना जताई है, पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी भेजने की आशंका जताई है, और कहा है कि नेपाल मार्ग से ये सारी गतिविधियां हो रही हैं, ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई है कि नेपाल के रास्ते से यहां आए कुछ आतंकवादियों को पनाह मिली है, बल्कि नेपाल ने ही हमें सूचनी दी थी, जो मोतिहारी के निकट हादसा हुआ था, उसमें नेपाल सरकार द्वारा हमें मदद मिली है। उन्होंने वहां 3 अपराधी arrest किए और उसकी सूचना भारत सरकार को दी। उनकी सूचना के आधार पर ही 6 आरोपियों को यहां पकड़ा गया है। ऐसे कुल 13 में से 9 आरोपी उस हादसे में पकड़े गए है। हमने NIA को जांच के लिए मामला सौंपा है। यह पहला मौका है, जब तीनों मामलों में NIA को जांच के लिए मामला सौंपा गया है। उनसे पूरी जानकारी मिलनी अभी शेष है, उनकी Report आनी शेष है। उसके बाद यदि कहीं पर ISI या अन्य किसी आतंकवादी संगठन का हाथ पाया जाएगा, उसके लिए steps लिए जाएंगे।

श्री संजय राउतः सर, मुम्बई जैसे बड़े शहर हमेशा आतंकवादियों के मुख्य target रहे हैं। इससे पहले भी मुम्बई की local trains आतंकवादी हमले की शिकार होती रही हैं, जिसमें हमारे हजारों लाखों लोग मारे गए हैं। Train में यात्रा करने वाले लोग या यात्री सुखद यात्रा का टिकट निकालते हैं, मौत का टिकट नहीं निकालते। हमने देखा है कि मुम्बई में बार-बार क्या होता है? कल ही मुम्बई के एक बड़े अख़बार में खबर आई है, IB सूत्रों के माध्यम से वह खबर publish हुई है कि मुम्बई में जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हैं, जैश-ए-मोहम्मद और लश्करे तैयबा के आतंकवादी, एक बार फिर देश में आतंकवाद फैलाने की फिराक में हैं और उनके निशाने पर मुम्बई से उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनें हैं — ऐसी IB की रिपोर्ट मुम्बई के अखबारों में publish हुई है। अगर इस रिपोर्ट पर विश्वास करें और सरकार के पास इसकी जानकारी है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि मुम्बई से यू.पी. जाने वाली और यू.पी. से मुम्बई आने वाली ट्रेनों की सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति महोदय, ऐसी जो भी जानकारी हमें किसी news के माध्यम से या Intelligence के माध्यम से मिलती है, उस पर सरकार तत्पर हो जाती है। संबंधित स्टेट या स्टेट्स को सूचनाएं भेज दी जाती हैं और निगरानी रखी जाती है। ऐसे हादसे successful न होने पाएं, विशेषकर हमारे सामने एक बड़ी समस्या यह भी है कि देश में रेलवे की जो लाइनें बिछी हैं, वे बहुत लम्बी हैं। लगभग 70 हजार किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनें देश में बिछी हुई हैं। सभी जगहों पर उनकी निगरानी रखना हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है। फिर भी, ऐसी जब कोई सूचना मिलती है, उस पर alert किया जाता है, सभी स्टेट्स की पुलिस की मदद भी

मांगी जाती है और कोशिश यह भी है कि हम Intelligence को और सक्षम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी सूचना भेजी गई है।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): जहां तक रेलों में चलने वाले यात्रियों और रेलवे ट्रैक्स की सुरक्षा का प्रश्न है, इस संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि पुलिस और Law and Order दोनों State subjects हैं। रेलवे ट्रैक्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की पुलिस की होती है। साथ ही साथ जिस राज्य से ट्रेनें गुजरती हैं, उनमें जो passengers होते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की होती है। इतना ही नहीं, बल्कि पूरे मामले की investigation की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की ही होती है। यदि राज्य सरकारें Central Government से यह अपेक्षा करती हैं कि किसी Central Agency के द्वारा किसी मामले की investigation कराई जानी चाहिए, तब हम उसे Central Agencies को भी देते हैं। कभी-कभी राज्य सरकारें recommend नहीं करती हैं, फिर भी यदि हमें लगता है कि किसी आतंकवादी संगठन का उसमें हाथ है, आतंकवादी गतिविधियां किसी मामले में प्रतीत होती हैं, तो हम सीधे भी NIA को उसकी जांच सौंपते हैं।

श्री सभापति: श्री प्रेम चन्द गुप्ता।

श्री प्रेम चन्द गुप्ता: श्रीमान् जी, माननीय गृह मंत्री जी इस सवाल का जवाब देने के लिए यहां हैं, यह अच्छी बात है। श्रीमान जी, मेरा कहना है कि यह रेल की पटरियों के साथ छेड़छाड़ का मामला नहीं है, बल्कि हमारा जो यूथ है, उसको गुमराह करने का यह एक नया तरीका निकाला गया है, जिसमें विदेशी एजेंसियां, जैसे हम बोल देते हैं कि आईएसआई ने यह करा दिया, पाकिस्तानी एजेंसीज़ ने यह करा दिया। आईएसआईएस वगैरह की जो ब्रांचेज़ हैं या इधर जो उनके स्लीपिंग सेल्स हैं, ये एक नई सोच डेवलप कर रहे हैं और इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान को मिलाकर एक नया मुल्क बनाने की यह एक नई चाल चली गई है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां घटना या दुर्घटना होने के बाद जो ऐक्टिव होती हैं, तो वे पहले क्यों नहीं उसमें preventive measures ले सकती हैं? श्रीमान् जी, आज टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है और पोलिटिशियंस के फोन्स टैप करने की बजाय अगर आपकी एजेंसीज़ इस तरह के एंटी-नेशनल एलिमेंट्स के फोन्स टैप करें या उनके....

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री प्रेम चन्द गुप्ता: श्रीमान् जी, मैं गृह मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपने ऐसा कोई प्रिवेंटिव सेल बनाया है, जिससे इस तरह की ऐक्टिविटीज़ को एडवांस में ही काउंटर करके उनको चेक कर दिया जाए?

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जहां तक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का सवाल है अथवा हमारी स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का सवाल है, उनमें इस समय mutual coordination है। उनके बीच coordination को लेकर कहीं किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। यदि स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कोई जानकारी हासिल होती है, तो वे हमारी सेंट्रल एजेंसीज़ को भी उससे अवगत कराती हैं और अगर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कोई जानकारी मिलती है, तो वे भी concerned स्टेट की एजेंसीज़ को वह जानकारी देती हैं। यदि कोई ऐसी जानकारी सामने आती है, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निश्चित रूप से

कुछ प्रिवेंटिव ऐक्शंस लिए जाते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है, लेकिन रेलवे सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे जो ऐसे कदम उठाए गए हैं, यदि आपकी इजाज़त होगी, तो उनकी जानकारी भी मैं यहां पर दे सकता हूँ, लेकिन इसमें लम्बा समय लगेगा। यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं जानकारी दे सकता हूँ।

श्री सभापतिः नहीं, उसकी जानकारी आप किसी दूसरे समय में दीजिएगा। आपने इनके सवाल का जवाब दे दिया है। दिग्विजय सिंह जी।

श्री दिग्विजय सिंहः महोदय, माननीय गृह मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि गोंडा की चुनावी सभा में 23 फरवरी को माननीय प्रधान मंत्री जी ने कानपुर की घटना के बारे में जो बयान दिया था, वह इस प्रकार से है — "Police have found a huge conspiracy which was hatched by the people sitting on the other side of the border." This is the statement of the hon. Prime Minister in his speech in Gonda. Sir, the question which hon. Sanjay Rautji has asked is, whether it is a fact that ISI and Pakistan-sponsored agencies are involved in such attacks. The answer is, the matter is under investigation, which means, Sir, the hon. Prime Minister is getting his reports directly from the NIA of which the hon. Home Minister is not aware of.

Sir, I would like to ask the hon. Home Minister whether it is a fact that the hon. Prime Minister was aware, when he made this speech in Gonda, that there is a specific hand of the ISI agencies and Pakistan in this sabotage of the Kanpur incident.

श्री राजनाथ सिंहः सभापति महोदय, हमारे देश में जो ये बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, वे हमारे पड़ोसी देश के द्वारा ही sponsored हैं। ऐसी अधिकांश घटनाएँ वहीं से sponsored हैं, इस हक़ीकत से सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। लेकिन, प्रधान मंत्री जी की जिस स्टेटमेंट की आपने चर्चा की है, उस संबंध में भी मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस प्रकार की खबरें समाचार-पत्रों में भी पहले आ चुकी हैं।

श्री दिग्विजय सिंहः प्रश्न इस बात का है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आप जवाब सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंहः माननीय प्रधान मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि इसमें आईएसआई का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है और आप कह रहे हैं कि इस संबंध में हमारे पास जानकारी नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजनाथ सिंहः प्रधान मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि इसमें सीधे आईएसआई का हाथ है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंहः उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो लिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आप जवाब सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंहः जब उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया है, ...**(व्यवधान)**..

श्री सभापतिः दिग्विजय सिंह जी, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

श्री दिग्विजय सिंहः माननीय गृह मंत्री जी उस बात को छिपा रहे हैं, जिसकी जानकारी हमारे प्रधान मंत्री जी को है।

श्री सभापतिः उनका जवाब सुन लीजिए।

श्री राजनाथ सिंहः मैं छिपा नहीं रहा हूं। मैंने पहले ही यह कहा कि जो भी आतंकवादी गतिविधियां यहां पर चल रही हैं, वह हमारे पड़ोसी देश के द्वारा स्पांसर्ड आतंकवादी गतिविधियां हैं। इसमें अधिकांश उनके द्वारा स्पांसर्ड हैं। **...(व्यवधान)...**

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, my question is: Is the NIA reporting directly to the Prime Minister or to the Home Minister?

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... That is not the question. ...(*Interruptions*)... You would need a separate question for that. ...(*Interruptions*)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, my question is simple. Is the Prime Minister or the Home Minister.. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)...

श्री राजनाथ सिंहः NIA पूरे मामले की जांच कर रही है दिग्विजय सिंह जी, आप प्रतीक्षा करिए, जांच पूरी होने दीजिए।

SHRI MANISH GUPTA: Mr. Chairman, Sir, we all know that when you have a security system, the integrity of the system is efficacious only if the system is able to give advanced information. Now, with regard to Railway security, I have noticed that there are a lot of Closed Circuit monitoring systems and railway stations are being monitored. But I think the involvement of the Railways and the State Governments should be more integrated. Many advanced countries today have systems and devices by which they can detect any disturbance on the railway tracks. If we are to depend on technology and if we have to build a modern society, we need to adopt these systems. I would like to ask the hon. Minister whether the Railways have got any plan to install such systems in the Railways.

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः महोदय, पहले ही बताया गया है कि ये सारी घटनाएं जो रेल से संबंधित हैं, आतंकी घटनाएं हों या उसकी सुरक्षा की, यह राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भी आपने जो कहा है, हमने पहले ही बताया है कि होम मिनिस्ट्री से नए-नए इक्विपमेंट लेने के लिए भी हम मदद करते आ रहे हैं। यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर भी हमने **...(व्यवधान)...**

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, how can we have railway tracks without involving the Railways? ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: One second, please. ...(*Interruptions*)... No, no. Please. ...(*Interruptions*)... Tapanji, please. This is not... ...(*Interruptions*)....

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, he did not understand the question. It is about integrating the... ..(*Interruptions*)... The State Government has to integrate these. Railway tracks are... ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*). This is not your question. Please listen to the answer.

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, इसके बावजूद भी मैंने अभी बताया था कि 31 जनवरी को हमारी मिनिस्ट्री से एक एडवाइजरी भेजी गई है, जिसमें स्टेट्स की इंटेलिजेंस को, उसके मैकेनिज्म को और भी सक्षम बनाने के लिए उसे सूचनाएं भेजी हैं। वहां जो अभी चर्चा हुई थी, उसमें हमने बहुत सी बातों पर सुझाव मांगे हैं। जिस दिन हमारी वीडियो काफ्रेंसिंग हुई थी रेल मंत्री जी के साथ में, सभी स्टेट्स को बताया गया कि वे रेलवे की सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव भेजें। उस पर रेल मंत्रालय और हमारा मंत्रालय बैठकर विचार करेंगे और हम साथ में जुड़कर उसमें काम करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इस मामले में राज्य सरकार की पुलिस को बहुत आगे आकर काम करना पड़ेगा। यह भी तय है कि जिन राज्यों से रेल गुजरती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है।

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, the question is entirely different. ...(*Interruptions*)... Sir, the question was about advanced technology to be introduced in the Railways. ...(*Interruptions*)... Why did he not reply? ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... I think the Minister said that consultations are taking place. ...(*Interruptions*)...

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, he has not answered the question.

MR. CHAIRMAN: The Minister did say that consultations with the Railway Ministry are taking place. Now, Question No. 213.

सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जम्मू और कश्मीर में आतंकी घटनाएं

*213. **चौधरी सुखराम सिंह यादवः** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि 'सर्जिकल-स्ट्राइक' के बाद जम्मू और कश्मीर में आतंकी घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) 'सर्जिकल-स्ट्राइक' के बाद कितने नागरिक एवं सुरक्षा कर्मी आतंकी घटनाओं में मारे गये हैं;

(ग) क्या कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा आतंकवादियों का समर्थन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे समर्थकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।